International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 9, September 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com Double-Blind
Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

कौशल विकास से भारत में बदलाव

डॉ0 केशरी नन्दन मिश्रा
एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास), हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय पी.जी. कालेज, नैनी, इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश

कौशल और ज्ञान किसी भी देश के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियाँ हैं जो किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास के निर्धारक होते हैं। जिन राष्ट्रों के पास अत्यधिक कुशल कार्यबल है, उन्होंने उत्पादकता और विकास में वृद्धि की है। भारत एक गतिशील मैक्रो-इकोनॉमिक वातावरण के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन का अनुभव कर रहा है, जिसमें देश के त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में आम सहमति बनाने के लिए स्पष्ट प्राथमिकताएं होंगी। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत गठित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने 2022 तक कुल 500 मिलियन लोगों में से 150 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने का काम सौंपा है, इसने प्रवीणता के कुछ नए क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सोलर पैनल से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स, वेस्ट मैनेजमेंट, ऑडिटिंग और असेसमेंट, रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी में सुधार और पब्लिक ट्रांजिट स्किल्स शामिल हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली हमारी 93 प्रतिशत श्रम शक्ति किसी भी औपचारिक कौशल विकास प्रणाली से रहित है। निकट भविष्य में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8% से 9% होने के अनुमान के साथ, यह आवश्यक है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र 10% से 11% की दर से बढ़े; यह मानते हुए कि कृषि क्षेत्र 4% की दर से बढ़ता है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में कार्यबल का प्रवास शामिल है।

प्रस्तावना

देश की प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास में सुधार के लिए मानव संसाधन बनाने के लिए उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में 29 वर्ष की औसत आयु के साथ सबसे युवा कार्यबल होने के जनसांख्यिकीय लाभ की क्षमता का एहसास करने के लिए कौशल विकास एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में उभरा है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन संस्थागत प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे, अभिसरण, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, विदेशी रोजगार, सतत आजीविका और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने पर ध्यान देने के साथ गति और मानकों के साथ बड़े पैमाने पर कौशल की कल्पना करता है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में कौशल कृषि क्षेत्र से भिन्न हैं। यह दर्शाता है कि प्रवास के कारण आने वाले वर्षों में कौशल अंतराल होगा जो केवल युवाओं के बड़े पैमाने पर कौशल विकास से भरा जा सकता है। राष्ट्रीय नीति 2022 तक लगभग 400 मिलियन कौशल और कौशल का लक्ष्य रखती है। यह देखते हुए एक बड़ी चुनौती है कि भारत में औपचारिक रूप से प्रशिक्षित का प्रतिशत कुल कार्यबल का 4.69 प्रतिशत है, जर्मनी जैसे देशों की तुलना में 75%, कोरिया 96 % के साथ है।

उद्योग की कौशल मांगों और युवाओं की आकांक्षाओं के बीच की खाई चौड़ी हो गई है, जिससे एक विरोधाभासी स्थिति पैदा हो गई है जहां उद्योग कुशल जनशक्ति की तलाश में है और कुशल युवा नौकरियों की तलाश में हैं। नवीनतम भारत कौशल रिपोर्ट इंगित करती है कि शैक्षणिक संस्थानों से निकलने वाले लगभग 47% ही रोजगार योग्य हैं।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 9, September 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com Double-Blind
Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

बहुप्रचारित कौशल योजना, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) पर हाल की रिपोर्ट बताती है कि नीति अभी भी अपने इच्छित परिणाम को प्राप्त करने से बहुत दूर है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, डेटा से पता चला है कि जून 2017 में देश भर में प्रशिक्षित या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 30.67 लाख उम्मीदवारों में से केवल 2.9 लाख को ही प्लेसमेंट के प्रस्ताव मिले थे।

कौशल विकास - अर्थ और फोकस

कौशल विकास का उद्देश्य आवश्यक और निरंतर उन्नत कौशल, ज्ञान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त योग्यता के साथ सशक्त रोजगार तैयार करना और गतिशील वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कार्यबल (मजदूरी और स्वरोजगार) की उत्पादकता और रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है। यह युवाओं, महिलाओं, विकलांगों और अन्य वंचित वर्गों की बढ़ी हुई भागीदारी और विभिन्न क्षेत्रों के प्रयासों में तालमेल बिठाने और बदलती प्रौद्योगिकियों और श्रम बाजार की मांगों के अनुकूल होने की बढ़ी हुई क्षमता के साथ वर्तमान प्रणाली में सुधार की मांग करता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार "एक सतत विकास प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में कौशल विकास का महत्वपूर्ण महत्व है और यह अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण को सुविधाजनक बनाने में योगदान दे सकता है। वैश्वीकरण के संदर्भ में बदलती अर्थव्यवस्थाओं और नई प्रौद्योगिकियों की नई मांगों को पूरा करने के लिए अवसरों और चुनौतियों का समाधान करना भी आवश्यक है।"

कौशल विकास एक "पुण्य चक्र" बनाने में मदद कर सकता है जिसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रासंगिकता नवाचार, निवेश, तकनीकी परिवर्तन, उद्यम विकास, आर्थिक विविधीकरण और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देती है जिससे अर्थव्यवस्थाओं को और अधिक नौकरियों के निर्माण में तेजी लाने की आवश्यकता होती है। .

कौशल विकास का वर्तमान परिदृश्य

भारत में केवल 5% छात्र ही व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह अन्य एशियाई देशों जैसे चीन, मलेशिया आदि की तुलना में काफी कम है। प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और योजना आयोग का कहना है कि सभी आर्थिक विकास में कौशल की कमी एक बड़ी बाधा है।

कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति, 2009 का लक्ष्य 2022 तक सभी व्यक्तियों को बेहतर कौशल, ज्ञान और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त योग्यता के माध्यम से सशक्त रोजगार तक पहुंच प्राप्त करने और वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए 500 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करना है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, विकलांगों, वंचित वर्गों के बीच संगठित और असंगठित क्षेत्रों में उत्पादन कार्यबल में वृद्धि करना है।

इसमें से 50 करोड़ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) 15 करोड़ को प्रशिक्षित करेगा, श्रम मंत्रालय 100 मिलियन, एमएचआरडी 50 मिलियन और शेष 23 करोड़ को 21 मंत्रालयों, विभागों और विभिन्न अन्य संगठनों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिकांश शिक्षित और अशिक्षित नौकरी चाहने वालों के पास कोई कौशल नहीं है। 90% रोजगार असंगठित क्षेत्र में है। 2020 तक, 220 मिलियन छात्र स्कूल से पास आउट हो जाएंगे - जिनमें से 150 मिल

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 9, September 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com Double-Blind
Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

कॉलेज शिक्षा के लिए नामांकन नहीं करेंगे; उन्हें व्यावसायिक व्यापार में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यहाँ तीन प्रकार के लक्ष्य समूह हैं -

कौशल विकास संकेतक क्या हैं?

कौशल और ज्ञान किसी भी देश के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की ताकत हैं। यह देखते हुए कि कौशल विकसित करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है, यह आवश्यक है कि किसी क्षेत्र/क्षेत्र/जिले/राज्य में कौशल विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले वास्तविक समय के आंकड़ों की उपलब्धता हो; उन क्षेत्रों की पहचान जहां कौशल विकास की सबसे अधिक आवश्यकता है; व्यक्तियों के कौशल श्रम बाजार में आवश्यक कौशल से कितनी अच्छी तरह मेल खाते हैं, और अब तक किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के परिणाम। कौशल विकास संकेतक (एसडीआई) देश भर में कौशल विकास पहलों के मूल्यांकन के उद्देश्य से विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध आंकड़ों को एक ही संसाधन के रूप में एक ही स्थान पर लाएगा। एसडीआई राज्यों को अपने स्वयं के पिछले प्रदर्शनों का मूल्यांकन और प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम करेगा और समय-समय पर संकेतकों में बदलाव की तुलना करने से राज्यों और विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के सुधार या प्रगति को ट्रैक करना संभव होगा। संकेतक विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा भी प्रदान करेंगे।

स्वतंत्रता पूर्व युग में कौशल विकास या व्यावसायिक प्रशिक्षण मौजूद नहीं था; वंश के माध्यम से केवल एक कौशल को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित किया जाता था। आजादी के बाद कुशल आबादी का एक मजबूत नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से कई एजेंसियों की स्थापना की गई। यद्यपि इस उद्देश्य के लिए कई पहलें/एजेंसियां स्थापित की गई हैं, फिर भी युवाओं को कुशल बनाना कई गुना चुनौतियां हैं।

भारत में कौशल विकास की प्रासंगिकता

जनसांख्यिकीय लाभांश: भारत में 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा युवा कार्यबल होने की उम्मीद है। एक समृद्ध जनसांख्यिकीय लाभांश के साथ, जहां 65% से अधिक आबादी कामकाजी आयु वर्ग की है, भारत के लिए इसका लाभ उठाने का यह एक उपयुक्त समय है। -समय की जनसांख्यिकीय खिड़की और इसके विकास को बढ़ाएं और दुनिया के बाकी हिस्सों में कुशल जनशक्ति की आपूर्ति करें।

प्रौद्योगिकी: प्रौद्योगिकी तीव्र गति से विकसित हो रही है और लाखों नौकरियों को खतरे में डालने की धमकी दे रही है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्वचालन से भारत में 69 प्रतिशत नौकरियों पर खतरा है। इसलिए, मौजूदा कार्यबल के साथ-साथ नए कर्मचारियों के लिए नई तकनीकों को फिर से तैयार करना और सीखना आवश्यक हो जाएगा; न केवल कार्यबल को बनाए रखने के लिए, बल्कि अर्थव्यवस्था के सफल डिजिटल प्रौद्योगिकी परिवर्तन को चलाने के लिए भी।

विनिर्माण: विनिर्माण उद्योग हाल के दिनों में एक उच्च विकास क्षेत्र के साथ-साथ एक प्रमुख रोजगार प्रदाता के रूप में उभरा है। परिवहन उपकरण, पेट्रोलियम और विद्युत मशीनरी जैसे कुछ विनिर्माण उद्योगों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और इसलिए, इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए मानव पूंजी का निर्माण आवश्यक है। इससे भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

उत्पादकता: विकसित देशों में बेरोजगारी और गिरती मजदूरी के उच्च स्तर का सामना करने के साथ, उभरते हुए देश अब विकास रणनीति के रूप में कम लागत वाले श्रम पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के

लिए एक कुशल, उत्पादक कार्यबल विकसित करने की आवश्यकता होगी।

कौशल विकास और आर्थिक प्रगति

कौशल विकास को दक्षता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे प्रशिक्षण या अनुभव के माध्यम से हासिल या विकसित किया जाता है। वैश्विक नेताओं ने अपनी राष्ट्रीय नीतियों के माध्यम से कौशल विकास की भूमिका और प्रभाव को स्वीकार किया है। यह व्यक्तियों की बदलती बाजार मांगों के अनुकूल होने और नवाचार और उद्यमशीलता गतिविधियों से लाभ उठाने की क्षमता को मजबूत करता है। कौशल विकास के प्राथमिक निर्धारकों के अलावा, प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में बदलती अर्थव्यवस्थाओं की नई मांगों को पूरा करने के लिए अवसरों और चुनौतियों का समाधान करना भी आवश्यक है।

देशों की भविष्य की समृद्धि अंततः रोजगार में व्यक्तियों की संख्या और वे काम पर कितने उत्पादक हैं, इस पर निर्भर करती है। यह एक गतिशील परिदृश्य है जहां सबसे सफल या प्रगतिशील राष्ट्र वह होंगे जो वीयूसीए (अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता, अस्पष्टता) (आबिदी और जोशी, 2015) का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए, कौशल विकास को व्यापक विकास, रोजगार और विकास से जोड़ा जा सकता है जो सरकारी हस्तक्षेप को अनिवार्य करता है।

निष्कर्ष

दरअसल, भारतीय युवा दो मुख्य समूहों में आते हैं। आर्थिक रूप से संपन्न मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को संगठित क्षेत्र में अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां मिलती हैं। भारत को अपने बड़े कार्यबल के कौशल का दोहन करने की आवश्यकता है ताकि बढ़ी हुई आर्थिक उत्पादकता और समावेशी सामाजिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस मोर्चे पर सरकार द्वारा कई पहल किए जाने के बावजूद; सभी कौशल पहलों के बेहतर समन्वय, एकीकरण और संरेखण की आवश्यकता है। भारत में, अधिकांश रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों और असंगठित क्षेत्र में है, और लगभग सभी निर्माण फर्म अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। श्रम बाजार की अत्यधिक स्तरीकृत और खंडित प्रकृति को देखते हुए, भारतीय युवाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल हासिल करना चाहिए, अगर उन्हें अच्छी नौकरी मिलनी है और किसी भी सामाजिक गतिशीलता का अनुभव करना है। इसके अलावा, प्रमुख चुनौतियों और अवसरों का लाभ उठाने के लिए नवीन दृष्टिकोण और समाधान लागू किए जाने चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि लोगों को कौशल विकास पहल करने के लिए संवेदनशील और प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। सरकार की पहल के बावजूद, इंजीनियरों और डॉक्टरों से ग्रस्त देश में, व्यावसायिक शिक्षा अभी भी अपनी हाशिए की छवि को छोड़ने के लिए संघर्ष कर रही है। इन पाठ्यक्रमों के बारे में धारणा सभी को स्वीकार्य बनाने में सबसे बड़ी चुनौती है। इन पाठ्यक्रमों को चुनने वाले छात्रों के लिए करियर पथ की कमी एक और बड़ी चुनौती है। इस पेपर ने भारत में हाल के तीव्र आर्थिक विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से युवा लोगों द्वारा प्राप्त कौशल के आधार पर उद्योगों की मांग के बीच एक विशाल कौशल अंतर की पहचान की है।

References

- Government of India *(2013-14). Education, Skill Development and Labour Force, Volume-3*. New Delhi: Labour Bureau, Ministry of Labour & Employment.
- UNESCO. (2012). *Education for All Global Monitoring Report 2012. Youth and Skills: Putting Education to Work*. Paris: UNESCO.

- Government of India (2012-13). *Seizing the Demographic Dividend- Chapter 2,* Economic Survey. New Delhi: Ministry of Finance.
- World Economic Forum. (2011). Global Competitiveness Report 2011/12. World Economic Forum.
- World Bank (2006), Skill Development in India – The Vocational Education and Training System, Human Development Unit, South Asia Region, January 2006
- Ashton, D. & Green, F. (1996). *Education, Training and the Global Economy*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Middleton, J., Ziderman, A. & Van Adams, A. (1993). *Skills for Productivity: Vocational Education and Training in Developing Countries.* New York: Oxford University Press.